अटल इंडस्ट्रियल मिशन से औद्योगिक विकास को रफ्तार की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिये औद्योगिक विकास को गति देने की मंशा से प्रदेश सरकार ने एक फंड बनाने की पहल की है। इस फंड का उपयोग कर औद्योगिक क्लस्टर, पार्क और जोन विकसित किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है।

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस संबंध में हाल ही में जारी गाइडलाइन में साफ किया गया है कि इस मिशन का उद्देश्य प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत औद्योगिक पार्क, क्लस्टर व जोन का विकास व उन्हें अपग्रेड किया जाएगा।

रेगुलेशन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर ईज आफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार किया जाएगा।

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के मानक तय

औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास पर फोकस किया जाएगा। मिशन के तहत सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण आवेदन के पात्र माने जाएंगे। प्राधिकरण मेगा फूड पार्कों के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय, पुनर्वास, नई सड़क, एक्सप्रेसवे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण व उच्चीकरण कराएंगे। बिजली क्षेत्र की आधारभूत संरचना का विकास, लाजिस्टिक व परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके दायरे में आएंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटी) का निर्माण और उच्चीकरण भी इसके तहत हो सकेगा।

औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी: औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी परियोजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। वहीं, औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी के रूप में परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे। समिति में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव-सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव व विशेष सचिव को भी जगह दी गई है। समिति परियोजना प्रस्तावों के आधार पर फंड का अनुमोदन व आवंटन करेगी। समिति द्वारा प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति और परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर समीक्षा व निगरानी की जाएगी।

संजय प्रताप सिंह बने लोनिवि विभागाध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: शासन ने संजय प्रताप सिंह को लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष बनाया है। उन्हें प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मुकेश चन्द्र शर्मा को प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।

संजय प्रताप सिंह अगले वर्ष जनवरी माह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस वर्ष जनवरी से लेकर दिसंबर तक लोक निर्माण विभाग में पांच विभागाध्यक्षों की तैनाती की जा चुकी है। जनवरी में एके जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद, वीके श्रीवास्तव, जेके बांगा व योगेश पवार के बाद संजय पांचवे विभागाध्यक्ष बने हैं। हालांकि शासन ने मुकेश के साथ श्रीराज का चयन प्रमुख अभियंता के लिए किया था। विभागीय सूत्रों के अनुसार श्रीराज के विरुद्ध एक मामले में जांच लंबित होने के कारण उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया गया।

सूत्रों के अनुसार फिलहाल जनवरी माह में विभाग को अगला विभागाध्यक्ष मिल सकता है। इस दौड़ में प्रयागराज में तैनात एके द्विवेदी का नाम आगे चल रहा है। महाकुंभ मेले के आयोजन के मद्देनजर फिलहाल उन्हें प्रयागराज से न हटाने का निर्णय लिया गया है।